संतुलित कारोबार का दौर

भारत में 1991 में शुरू किए गए 'पहली पीढ़ी' के आर्थिक सुधारों से भारत के प्रति अमेरिकियों और अमेरिकी कंपनियों के नजरिए में दूरगामी परिवर्तन हुआ। देश के बंद, स्थिर अर्थव्यवस्था से खुली, बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के साथ ही अमेरिका की भारत में, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सेवा क्षेत्रों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। आज अमेरिका भारत का अहम व्यापारिक साझीदार है। अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक, भारत में करीब 1,000 अमेरिकी कंपनियां व्यापार कर रही हैं, यह संख्या 1991 के मुकाबले 14 गुना ज्यादा है।

जाहिर है, अमेरिका-भारत संबंधों को साझीदारी का नया और गतिशील क्षेत्र मिल गया है। जीई इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ स्कॉट आर. बेमैन कहते हैं, ''अब भारत की बौद्धिक प्रतिभा के विशाल वर्ग को व्यापक स्वीकार्यता मिल रही है। अब मुझे भारत की विशेषताओं का गुणगान करने की जरूरत नहीं पड़ती।'' भारत में तेजी से विकास कर रही अमेरिकी कंपनी के प्रमुख के नाते बेमैन निश्चित ही इस बारे में बेहतर जानते हैं। जीई इंडिया ने 1990 के दशक में तेजी से विकास किया। उसके 31 कारोबार हैं जिनकी भारत में सालाना बिक्री 4,600 करोड़ रु. (1 अरब डॉलर) है। लेकिन यह भी सही है कि कारोबार संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में ही है और हाल में भारत में अमेरिका का निवेश तथा निर्यात अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। जाहिर है, बदले हुए आर्थिक संबंधों में अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं के अधिकाधिक बाजार के अवसरों की कमी है। दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डालने के लिए आंकड़ों की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्डों और टीवी विज्ञापनों, आलीशान मॉल और किराना दुकानों, मल्टीप्लेक्स और सड़क के किनारे लगे विज्ञापन बोर्डों पर दिखने वाले अमेरिकी ब्रांड आज घर-घर में परिचित हैं। आज मैकडोनाल्ड के मेनु और डोमिनो के पिज्जा पारंपरिक भारतीय खानपान की दुकानों से होड़ लगा रहे हैं। नाइक और रीबोक भारतीयों के चलने और कसरत करने का अंदाज बदलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और भारत में अमेरिका के प्रमुख निर्यातक हॉलीवुड ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के विश्व प्रीमियरों में भारत को भी शामिल कर लिया है। अमेरिका अब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश, दोनों ही मामलों में भारत में सबसे बड़ा निवेशक है। डूपोंट के दक्षिण एशिया के अध्यक्ष हेनरिक एच. उब्रिग कहते हैं, ''दोनों देशों के बीच बढ़ता आर्थिक सहयोग एक-दूसरे के बाजारों की असली कीमत समझने का नतीजा है।''

रफ्तार धीमी होने के बावजूद दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार इन आर्थिक संबंधों को और मजबूती देने का भरोसा देते हैं। भारतीय संसद ने 2002-2003 में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, दिवालिया कानून और इक्विटी बाजार नियमन पर केंद्रित 35 से अधिक विधेयक पारित किए। एक ओर जहां प्रतिस्पर्धा विधेयक से एकाधिकार को पुन:परिभाषित करने की कोशिश की गई है, वहीं मनी लॉन्डरिंग बिल एवं उपभोक्ता

आज करीब 1,000 अमेरिकी कंपनियां भारत में अपना कारोबार कर रही हैं

भारत की उदारीकृत अर्थव्यवस्था में अमेरिकी कंपनियां फल-फूल रही हैं

अमित गुप्ता/रायटर

विकास नरूला

नई दिल्ली में शेवरले सेलिब्रेशन रैली में अमेरिकी राजदूत डेविड सी. मलफोर्ड (दाएं) और जनरल मोटर्स इंडिया के अध्यक्ष आदित्य विज

संरक्षण विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ताओं के साथ ही नीतिगत कारोबार के लिए जीवन आसान बनाना है। इस पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की कामयाबी अमेरिका की उन कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो व्यापार, निवेश और अमेरिका-भारत संबंधों में टिकाऊ वृद्धि के लिए निवेश सीमा हटाने, आयात शुल्क कम करने, खुदरा बिक्री पर पाबंदियां और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण को खत्म करने को जरूरी मानते हैं।

निस्संदेह, आईटी में भारत की महारत और पहचान उसके बदलते चरित्र की प्रतीक है, जिससे दोनों देशों के संबंधों को निर्णायक बढ़त मिली है। जीई का बंगलोर स्थित जॉन एफ. वेल्च टेक्नोलॉजी सेंटर प्रौद्योगिकी विकास और परीक्षण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसी तरह तीसरी पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकी में ल्यूसेंट का सारा मौलिक काम भारत में ही होता है। भारत में इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर को सन् 1999 में मात्र 10 कर्मचारियों के साथ शुरू किया गया था। आज इसमें 1,000 से ज्यादा इंजीनियर हैं। कारनेगी मैलन यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने दुनिया की केवल 48 सॉफ्टवेयर कंपनियों को अपनी उच्च गुणवत्ता वाली रैंकिंग में रखा है; उनमें से करीब दो-तिहाई कंपनियां भारत में स्थित हैं।

पिछले पांच साल से सेवाओं में भारत के कुल निर्यात में सालाना 21.5 फीसदी की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। सॉफ्टवेयर की बदौलत आउटसोर्सिंग और सॉफ्टवेयर से जुड़ी सेवाओं का निर्यात, जो 40 फीसदी की सालाना औसत दर से बढ़ा, भारत में आला दर्जे की नई अमेरिकी अनुसंधान सुविधाओं के विस्तार से इसमें और गति आई है। जीई कैपिटल के प्रमुख प्रमोद भसीन कहते हैं, ''भारत हमें विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाने के मामले में अहम हो गया है।'' कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों के भारत में बैक-ऑफिस काम करने से सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का तेजी से बढ़ता घटक बन गया है।

पोर्टफोलियो निवेशक, उपक्रम पूंजी कोष और बैंकों के रूप में अधिकाधिक अमेरिकी कंपनियां भारत में आ रही हैं। आज सिटी बैंक भारत का सबसे बड़ा क्लियरिंग बैंक है और उसी ने सर्वाधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। इसी तरह अमेरिकन एक्सप्रेस, जिसने भारत में बैक-ऑफिस काम करने का प्रचलन शुरू किया, ने जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की और फिलहाल भारत में उसके करीब 3,000 कर्मचारी हैं।

आर्थिक सुधारों से बीमा क्षेत्र भी खुलने लगा है, जिसमें हाल तक विदेशी निवेश पर पाबंदी थी। आज कम-से-कम पांच बड़ी अमेरिकी बीमा कंपनियां संयुक्त उपक्रमों के जरिए भारत में कारोबार कर रही हैं। इसी दौरान, उत्तर अमेरिका में पेंशन मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी प्रिंसिपल फाइनेंशियल ग्रुप ने कम-से-कम 4,00,000 उपभोक्ता बना लिए हैं और भारत में लगभग 70 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। यह कंपनी बड़े पैमाने पर साझा कोष का कारोबार करती है। भारत में इस क्षेत्र को 1990 के दशक के मध्य में निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था। अब पेंशन क्षेत्र के भी निजी खिलाड़ियों के लिए खोले जाने के साथ ही यह कंपनी 2004 के मध्य से अपनी पेंशन योजनाएं बेचना शुरू कर देगी। प्रिंसिपल फाइनेंशियल ग्रुप के कंट्री मैनेजर संजय सचदेव कहते हैं, ''कारोबार की सुविधा मुहैया कराने के प्रति सरकार के बदलते रवैए से अमेरिकी कंपनियों को मदद मिली है।''

अमेरिका ने भारत में नियामक संस्थाओं को सुदृढ़ करने में भी रणनीतिक भूमिका निभाई है। भारत में यूएसएड के 667 करोड़ रु. (14.5

उक्ति

"लोकतांत्रिक सरकारें ऐसी परिस्थितियां तैयार करती हैं जिनसे कारोबार जगत और लोग पहल करने को प्रेरित होते हैं।"

—डेविड सी. मलफोर्ड, अमेरिका के राजदूत, अप्रैल, 2004 मुंबई में

डूपोंट

चमकीला भविष्य

देश में बेहतरीन नियोक्ताओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध और तेजी लेकिन खामोशी से विकास करने वाली कंपनी डूपोंट के विभिन्न प्रकार के उत्पाद लाखों भारतीयों के जीवन में शामिल हो रहे हैं

भारत में डूपोंट ने तेजी से विकास किया। भारत में सन् 1974 में संपर्क कार्यालय खोलने वाली कंपनी 1994 में पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बन गई। आज भारत में इसके 600 कर्मचारी, 3 स्थानों पर 6 निर्माण इकाइयां और करीब 1,000 करोड़ रु. (21.5 करोड़ डॉलर) का राजस्व है और इसने पिछले 5 साल में सालाना 15 फीसदी की दर से विकास किया। पिछले साल भारत आए डूपोंट के अध्यक्ष और सीईओ चार्ल्स ओ. हॉलीडे जूनियर की घोषणा के मुताबिक, कंपनी का सन् 2005 में 1,500 करोड़ रु. (32.5 करोड़ डॉलर) बिक्री का लक्ष्य है। कंपनी को मानव संसाधन फर्म हेविट एसोसिएट्स की सन् 2003 में की गई रैंकिंग में भारत में उम्दा नियोक्ताओं में जगह मिली।

भारत में डूपोंट की उत्पाद श्रृंखला इसके वैश्विक पोर्टफोलियो का ही प्रतिरूप है। इसके अधिक प्रतिरोध क्षमता वाले इंजीनियरिंग पॉलीमर को भारतीय रेलवे प्रयोग करती है, इसके आधुनिक किस्म के फाइबर से बुलेट-प्रतिरोधी जैकेट बनाए

भारत में डूपोंट के छह संयंत्रों में से एक

साभारःई.आइ. डूपोंट इंडिया प्रा. लिमि.

जाते हैं, इसके औद्योगिक पॉलीमर को जम्मू-कश्मीर की कठिन परिस्थितियों में सड़कों पर परखा जा रहा है। और इसके टेफ्लॉन ® लेप वाले नॉन-स्टिक कुकवेयर भारतीय घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं। डूपोंट के कई तरह के कीटनाशक, खरपतवारनाशक, कृषि एवं पोषण के उत्पाद भी हैं। डूपोंट के दक्षिण एशिया के अध्यक्ष हेनरिक एच. उब्रिग कहते हैं, ''डूपोंट अपने विश्वव्यापी विकास के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान दे रही है और भारत इसमें अहम है।'' कंपनी भारत की संभावना भरी अनुसंधान क्षमता को परख रही है। जैव-प्रौद्योगिकी ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंपनी काफी मौके देख रही है। डूपोंट अपने आविष्कारों के लिए पेटेंट मसौदों की योजना बना रही है और इन क्षेत्रों में बड़े भारतीय विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक संस्थानों से गठजोड़ की संभावनाएं तलाश रही है।

उब्रिग कहते हैं, ''डूपोंट की भावी प्रगति एशिया प्रशांत क्षेत्र में है, जहां दो अंकों में विकास हो रहा है।'' भारत में सुरक्षा सलाहकार सेवा शुरू करने वाली कंपनी इंजीनियरिंग और औद्योगिक पॉलीमर व ऑटोमोटिव कोटिंग के साथ ही कृषि, खाद्यान्न और पोषण के कारोबार को विकास के साधन के रूप में देखती है।

'सपोर्ट-अ-स्कूल' कार्यक्रम

प्रगति में भागीदारी

अमेरिकी कंपनियां वंचित वर्गों को आईटी में बढ़त का फायदा दिलाने के लिए तैयारी कर रही हैं। कंपनियों के स्कूलों को प्रायोजित करने के साथ ही डिजिटल विभाजन धीरे-धीरे खत्म हो रहा है।

नरेंद्र बिष्ट/इंडिया टुडे

अमेरिकी कंपनियों ने दिल्ली की बस्ती गोविंदपुरी (ऊपर) तथा फिल्मनगर, हैदराबाद के बच्चों के लिए नई दुनिया के द्वार खोले हैं

हैदराबाद में यह बरसाती बुधवार है। सतत बारिश से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पर कई छात्र फिल्मनगर स्लम स्कूल में पहुंचे हैं। उनकी रिसती, जर्जर झोंपड़पट्टियों से अलग सीमेंट से बना यह स्कूल सुरक्षित है। पर स्कूल आने की यह सिर्फ एक वजह है। अच्छे शिक्षक, गर्मागर्म खाना, पेय जल व स्वच्छ शौचालय उससे भी बड़े प्रलोभक हैं। यह बदलाव एक कॉर्पोरेट प्रायोजक, अमेरिका स्थित पोर्टलप्लेयर प्रा. लि. की भारतीय सब्सिडियरी की बदौलत हुआ।

पोर्टप्लेयर समेत आठ अमेरिकी कंपनियां नांदी फाउंडेशन के सपोर्ट-अवर-स्कूल (एसओएस) कार्यक्रम के तहत स्कूलों को प्रायोजित करती हैं। पोर्टप्लेयर के प्रबंध निदेशक जे.ए. चौधरी कहते हैं, ''हमारा उद्योग ज्ञान-आधारित है और हम अपने समाज में खाई पाटने के लिए शिक्षा संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।'' हैदराबाद के 10 स्कूलों में शुरू हुई यह परियोजना जल्दी ही 882 स्कूलों में फैल जाएगी।

सामाजिक प्रतिबद्धता वाली अमेरिकी कंपनियां बदलाव का उत्प्रेरक बन रही हैं। दिल्ली की गोविंदपुरी में स्वयंसेवी संगठन कथा के साथ इंटेल ने एशिया का पहला युवा केंद्र स्थापित किया है। यह वंचित वर्ग के बच्चों को आईटी प्रोग्राम और लैंग्वेज सिखाकर डिजिटल खाई पाटने की कोशिश कर रहा है। कंप्यूटरों और वेब-कैम के साथ यह उन्हें 21वीं सदी का हिस्सा दे रहा है। इंटेल इंडिया को सन् 2003 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जिम्मेदार कंपनी, सक्रिय सामुदायिक भूमिका और कर्मचारियों से अच्छे बरताव के लिए मान्यता दी। ये खूबियां अमेरिकी कंपनियों की जनसेवा की शानदार परंपराओं की द्योतक हैं।

करोड़ डॉलर) के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वित्तीय संस्थान सुधार एवं विस्तार (फायर) परियोजना ने भारत की पहली प्रतिभूति डिपॉजिटरी, नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि. बनाने में मदद की है और देश के पूंजी बाजारों की कार्यक्षमता विश्वस्तरीय बनाने की प्रक्रिया तेज की है। उसने एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के साझा कोषों के प्रदर्शन के बारे में रिपोर्टिंग को स्तरीय बनाने में भी मदद की और भारत के बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को भावी व वैकल्पिक बाजार शुरू करने के लिए ढांचा तैयार करने में सहयोग किया।

तेजी से वैश्विक होती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर यह विनिमय दोतरफा है। भारतीय कंपनियां अमेरिका में कारोबार कर रही हैं और अमेरिका के इक्विटी बाजारों से पूंजी उगाह रही हैं। फिलहाल, कम-से-कम 10 भारतीय कंपनियां न्यूयॉर्क शेयर बाजार (एनवाईएसई) और नैस्डेक में सूचीबद्ध हैं। भारत की चोटी की आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के उपभोक्ताओं में बोईंग, सिस्को और डेल शामिल हैं। सत्यम् कंप्यूटर्स के दुनिया भर में 280 उपभोक्ता हैं, जिनमें 81 फॉर्च्यून 500 कंपनियां शुमार हैं। हाल ही में उसने ई-मेल सॉल्यूशंस के साथ एक पोर्टल बनाने के लिए याहू! के साथ साझीदारी का करार किया है। यह कंपनी सर्चपैड नामक एक नया इंटरनेट सर्च इंजन भी तैयार कर रही है।

इसके मुकाबले निर्माण क्षेत्र और उपभोक्ता बाजार की रफ्तार धीमी है, हालांकि हाल में उनका विकास तेज हुआ है। मिसाल के तौर पर भारत में मैकडोनाल्ड ने 13 अक्तूबर 1996 को दिल्ली में अपना पहला बर्गर बेचा था। सन्

अजीत कुमार/एपी फोटो

आज मैकडोनाल्ड भारतीय युवाओं के लिए एक जाना-पहचाना नाम बन चुका है

2003 में भारत में मैकडोनाल्ड के 40 आउटलेट खुले और कंपनी ने 4.5 करोड़ चिकन और वेजिटेरियन बर्गर बेचे। अमेरिका की इस खानपान की शृंखला की दुकानों में हर रोज 1,50,000 भारतीय उपभोक्ता जाते हैं। दुनिया में भारत ही ऐसा अकेला देश है जहां स्थानीय संस्कृति के प्रति संवेदनशील मैकडोनाल्ड गोमांस के उत्पाद नहीं बेचती।

भारतीय बाजार की जरूरतों के मुताबिक ढलकर कई अमेरिकी कंपनियों, खासकर मैकडोनाल्ड, डोमिनो, पिज्जा हट, पेप्सी, कोका-कोला, रिबोक, नाइक, एमवे और एवन सरीखी खानपान की शृंखलाओं और उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों ने भारत में अपनी उपस्थिति बड़े पैमाने पर दर्ज कर ली है। पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्रा. लि. के अध्यक्ष राजीव बख्शी कहते हैं, ''भारत में पेप्सी का अनुभव बहुत-बहुत सकारात्मक रहा है। भारत उन तीन उभरते बाजारों में शुमार है जिन पर हम काफी दांव लगा रहे हैं।'' भारत में कृषि व्यापार समेत पेप्सी के कारोबार में कुल निवेश लगभग 4,500 करोड़ रु. (1 अरब डॉलर) है।

डूपोंट का अनुभव भी इतना ही उत्साहजनक है। कंपनी ने सन् 1974 में भारत में संपर्क कार्यालय खोला था, जो अब बढ़कर मूल कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी बन गया है। इसकी औसत वार्षिक विकास दर 15 फीसदी है। डूपोंट पोषण, हेल्थकेयर और निर्माण समेत बाजार के विभिन्न हलकों में कई तरह के उत्पादों

भारत में अमेरिकी निवेश का क्षेत्रवार ब्यौरा

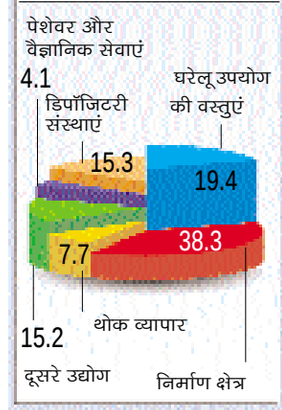

स्रोतः यू.एस. सेंसस ब्यूरो

का विपणन करती है। 1,000 करोड़ रु. (21.5 करोड़ डॉलर) की भारतीय सब्सिडियरी के पास भारत में तीन जगहों पर छह निर्माण इकाइयां हैं। उसके करीब 600 कर्मचारी हैं और उसने अतिरिक्त 2,500 लोगों के लिए परोक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।

यह 1990 के दशक के शुरू में मौजूद स्थितियों के मुकाबले बिल्कुल अलग स्थिति है। उस समय ऐसे विस्तार की संभावना नगण्य थी। तब से भारतीय बाजार में नाटकीय परिवर्तन हुआ है। आय का स्तर बढ़ने, रवैयों में बदलाव आने और अधिकाधिक शहरी जीवन-शैली अपनाने के साथ ही घरेलू बाजार तेजी से फैल रहा है। कंप्यूटर, दूरसंचार के उपकरण, मोबाइल फोन और रंगीन टेलीविजन जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ रहे बाजारों में से एक है। सन् 1991 और 2001 के दौरान पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) और पेरीफेरल का बाजार 13 गुना बढ़कर 719 करोड़ रु. (15.6 करोड़ डॉलर) से 9,684 करोड़ रु. (2.1 अरब डॉलर) हो गया। इसी परिवर्तन के कारण अमेरिका की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत को निर्माण आधार के रूप में परखने के लिए प्रेरित हो रही हैं। पांच साल पहले भारत वाल-मार्ट के रडार पर कहीं नजर नहीं आता था। आज वाल-मार्ट भारत से 1,840 करोड रु. (40 करोड़ डॉलर) के उत्पाद लेता है और कुछ आकलनों के मुताबिक अगले तीन-चार साल में यह आंकड़ा 4,600 करोड़ रु. (1 अरब डॉलर) तक पहुंच सकता है। वाल-मार्ट के महाप्रबंधक पी. जगन्नाथन कहते हैं, ''फिलहाल हम चीन पर बहुत ज्यादा आश्रित हैं। भारत एक अच्छा विकल्प दिखता है।''

शिप्रा दास/इंडिया टुडे

यूएसटीआर रॉबर्ट जोएलिक (दाएं) सीआईआई के तत्कालीन अध्यक्ष संजीव गोयनका के साथ

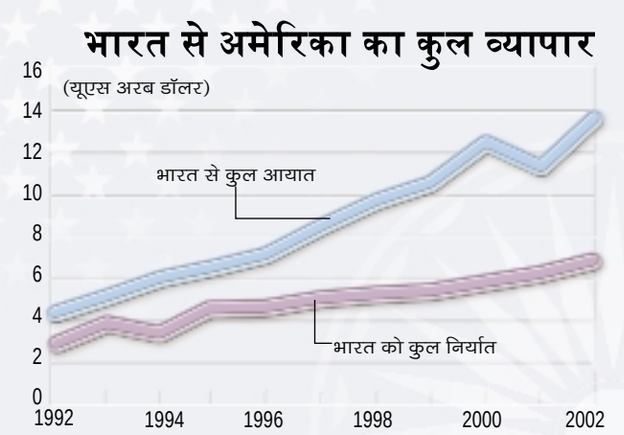

बढ़ते वाणिज्यिक संबंधों के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच सरकारी स्तर पर अधिकारियों की आवाजाही भी बढ़ गई है। सितंबर 2001 के बाद से मंत्रिमंडल के कई सदस्यों समेत अमेरिका के 100 से अधिक आला दर्जे के अधिकारियों ने भारत का दौरा किया है। कई लोगों ने आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर ध्यान दिया है। बाजार में पहुंच के मुद्दों और दूसरी समस्याओं की पहचान करके उन्हें सुलझाने के लिए मजबूत संस्थागत संबंध विकसित करने की खातिर नई दिल्ली और वाशिंगटन के अधिकारियों के बीच आमने-सामने की मुलाकातें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सामान्य बात हो गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के महासचिव अमित मित्रा का कहना है, ''हम पहले के मुकाबले ज्यादा संवाद कर रहे हैं और बातचीत उच्चतम स्तर पर हो रही है।''

अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नवंबर 2001 में

विवान मेहरा

एमवे

आगे बढ़ते कदम

कारोबार में उदारवादी माहौल और भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ से इस अमेरिकी कंपनी को भारत में बिक्री का अपना नेटवर्क फैलाने में मदद मिली है।

एमवे इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ विलियम एस. पिंकनी को अपने उत्पाद सीधे बेचने के लिए भारत सरकार की मंजूरी लेने में तीन साल लगे। एमवे मुख्यतः पर्सनल केयर और घरेलू वस्तुओं का विपणन करती है पर आयात पर प्रतिबंध, अधिक शुल्क व केवल लघु उद्योगों के लिए आरक्षित निर्माण नीति से व्यावसायिक माहौल दोस्ताना नहीं था। पर पिंकनी और उनके दल ने धीरज बनाए रखा।

उन्हें धीरज का फल मिला। आज भारत एमवे के सबसे तेजी से बढ़ते 10 बाजारों में से एक है। यहां कारोबार शुरू करने के पांच साल बाद कंपनी के 350 कर्मचारी व देश में फैले 48 कार्यालयों तथा 97 गोदामों से जुड़े 3,50,000 वितरक हैं। पिंकनी कहते हैं, ''अगले तीन साल में भारत हमारे पांच प्रमुख बाजारों में से एक होगा।''

एमवे के उत्पाद अमेरिका में 450 वैज्ञानिक विकसित करते हैं और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इन्हें अत्याधुनिक कारखानों में निर्मित किया जाता है। पिंकनी कहते हैं, ''हमें अपने उत्पाद भारत में ही बनाने को कहा गया और वह भी लघु उद्योग के रूप में।'' लेकिन इससे उसे भारतीय बाजार की जरूरतों और मांगों के अनुरूप ढलने में मदद मिली।

भारत में बदला कारोबारी माहौल मददगार है, शुल्क घटे हैं और एक उदार विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड है जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। पिंकनी कहते हैं, ''आप यहां पहले के मुकाबले खुद को ज्यादा स्वागतेय महसूस करते हैं। यह अहम है, वैसे बाहर धारणा खास नहीं बदली है। बदलाव देखने के लिए यहां आना होगा।''

एमवे का कारोबार बढ़ रहा है

द्विपक्षीय आर्थिक वार्ता दोबारा शुरू की, जिसे आर्थिक मुद्दों पर संवाद के लिए सबसे महत्वाकांक्षी और ठोस चैनलों में से एक करार दिया गया। इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार के चार व्यापक क्षेत्रों—पर्यावरण, वित्त, ऊर्जा और वाणिज्य—में आधिकारिक साझीदारी मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा।

भारत-अमेरिकी संबंध, भारत को परमाणु अप्रसार की समस्या के बतौर तथा द्विपक्षीय संबंधों को हमेशा भारत-पाकिस्तान के चश्मे से देखे जाने से कहीं आगे निकल गए हैं। दृष्टिकोण में इस बदलाव की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की सन् 2000 में भारत यात्रा के बाद हुई। राष्ट्रपति बुश की मौजूदगी में ये संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। सन् 1994 में द्विपक्षीय व्यापार 8 अरब डॉलर का था जो 2003 में बढ़कर 82,800 करोड़ रु. (18 अरब डॉलर) हो गया। भारत में अमेरिका का निर्यात, जो लंबे अरसे तक स्थिर रहा, में सन् 2003 में 19 फीसदी का इजाफा हुआ और यह पहली बार 4 अरब डॉलर को पार कर गया। 2003 में भारत में अमेरिका का निर्यात साल-दर-साल के आधार पर 18 फीसदी बढ़कर 4.4 अरब डॉलर हो गया जबकि भारत से अमेरिका में आयात 11 फीसदी बढ़कर 13 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। अमेरिका का प्रत्यक्ष निवेश भी बढ़कर रिकॉर्ड 3.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अमेरिका के वाणिज्य उपमंत्री सैमुअल डब्लू. बॉडमैन ने 2003 के शुरू में भारत दौरे के समय इस वृद्धि को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, ''एक साल पहले तक मैं भारत में कम अमेरिकी निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर अफसोस

उक्ति

"मेरा मत है कि लंबे अरसे में अमेरिका-भारत संबंधों को जो बात परिभाषित करेगी, वह उसका आर्थिक पहलू ही है।"

—अल लार्सन, अमेरिका के आर्थिक, कारोबार और कृषि संबंधी मामलों के अवर मंत्री, 15 मार्च, 2004

गुरिंदर ओसन/एपी फोटो

भारतीय अर्थव्यवस्था आपूर्ति नहीं बल्कि उपभोक्ता प्रेरित हो रही है

अमेरिकी कंपनियों की शिकायत

- भारत सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप।
- अधिक सीमा शुल्क और अत्यधिक परोक्ष कर।
- भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों के लिए करों की अलग दर।
- विदेशी निवेश करने पर पाबंदियां।
- खराब बुनियादी संरचना।
- ''ठेके के औचित्य'' के बारे में सवाल।
- बौद्धिक संपदा की कमजोर सुरक्षा।

जाहिर करता था। इस साल मैं कुछ अच्छी खबर दे सकता हूं।''

इसके अलावा, 9/11 के बाद भारत-अमेरिकी आर्थिक संबंधों में तत्परता की भावना आ गई है। अमेरिका के वाणिज्य अवर मंत्री केनेथ जस्टर ने कहा, ''मजबूत, जीवंत व मुक्त अर्थव्यवस्था वाला भारत एशिया और दुनिया भर में अपना प्रभाव डालने में ज्यादा सक्षम होगा तथा एशिया में शांति, स्थिरता एवं आतंकवाद से लड़ने के हमारे साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में ज्यादा प्रभावी होगा।'' दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों में बाहरी कारकों का केवल आंशिक प्रभाव ही है। भारत जब से विदेशी निवेश और आयात के लिए ज्यादा उपयुक्त माहौल बनाने की दिशा में आगे बढ़ा है, भारतीय नेताओं में विश्व अर्थव्यवस्था के साथ पूरी तरह तालमेल बनाए रखने के महत्व की स्वीकार्यता बढ़ी है।

भारत का अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त बनाने का प्रयास धीमा है, लेकिन वह निरंतर जारी है। अमेरिकी सरकार और कंपनियों ने इन प्रयासों का स्वागत किया है। भारत ने सन् 2000 में कई उत्पादों पर संख्यात्मक प्रतिबंध हटाकर अमेरिकी निर्माताओं के लिए नए दरवाजे खोल दिए। इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। जब अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी सप्लायरों से मिलने के लिए कृषि उपकरणों के भारतीय खरीदारों का एक व्यापारिक दल ले जाने की योजना बनाई, तो शुरू में उस प्रतिनिधिमंडल में केवल 12 भारतीय कंपनियों को शामिल करने का लक्ष्य था। लेकिन जब यह मिशन मई 2002 में रवाना हुआ, तो उसमें 36 प्रतिनिधि थे और 10 प्रतीक्षा सूची में थे। कारोबार की घड़ी टिकटिक करने लगी है और भविष्य संभावनाओं से भरा लगता है।

लेकिन बौद्धिक संपदा के अधिकारों की रक्षा समेत कई मुद्दों को सुलझाया जाना अभी बाकी है। भारत के पेटेंट कानूनों में उत्पाद पेटेंट के उलट फिलहाल प्रक्रिया पेटेंटों को ही मान्यता हासिल है, जिससे स्थानीय कंपनियां दवाओं की नकल तैयार कर लेती हैं। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि यह स्थिति बदल जाएगी। डब्लूटीओ की शर्तों के मुताबिक भारत को सन् 2005 तक अपने पेटेंट कानूनों में संशोधन करना होगा। ऐसा होने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास भारत में कम लागत पर निर्माण करने के लिए इकाइयां लगाने का बेहतर आधार होगा।

अमेरिका और भारत के बीच जारी व्यापार असंतुलन को पूरी तरह दुरुस्त करने की जरूरत है। जैसा कि देखा गया है, 2003 में अमेरिका को 8.7 अरब डॉलर का घाटा था, जो 2002 के मुकाबले 7 फीसदी ज्यादा है। दूसरी ओर सन् 1995 के बाद भारत से अमेरिका को आयात दोगुना से भी ज्यादा हो गया है। अमेरिकी सरकार और अमेरिकी उद्योग इसके लिए अधिक सीमा शुल्क, कर और भारतीय बाजार में मौजूद नियमन संबंधी पाबंदियों को जिम्मेदार मानते हैं। डिप्टी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रजेंटेटिव (यूएसटीआर) जॉन एम. हंस्टमैन जूनियर का कहना है, ''ये प्याज के छिलके जैसे बहुस्तरीय अवरोधक संभावित निर्यातकों को हतोत्साहित करते हैं।''

अमेरिका के निवेशक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा, अधिकाधिक सीमा शुल्क और गैर-सीमा शुल्क के अवरोधकों से संबंधित भारत की प्रतिबंधात्मक नीतियों के बारे में लंबे अरसे से शिकायत करते रहे हैं। श्रम सुधारों समेत आर्थिक सुधारों के ''दूसरे दौर'' से भारत को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनने में मदद मिलेगी और इससे अमेरिकी व्यापार को भी अधिक बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका-भारत के आर्थिक संबंधों का यह क्षेत्र रिश्तों को नया रूप देने के लिए जरूरी है।

फोर्ड

सुहाना सफर

यूरोप और अमेरिका में बिक्री स्थिर होने के साथ ही फोर्ड भारतीय बाजार की ओर देख रही है। भारत में उसका नया सफर कम लागत, अधिक गुणवत्ता वाले उत्पादन से प्रेरित है।

भारत में वाहन उद्योग के लिए बढ़िया दौर है। 1995 में भारत पहुंची फोर्ड इंडिया ने 2003 में 24,000 कारों के निर्यात समेत करीब 43,000 कारें बेचीं, और साल भर पहले के मुकाबले उसकी बिक्री 24 फीसदी बढ़ गई। क्या इससे एक ऐसे वैश्विक वाहन उद्योग के अग्रणी के बोर्डरूम में दिलचस्पी पैदा हुई, जिसने 2002 में 7,47,960 करोड़ रु. (162.6 अरब डॉलर) का कारोबार किया और 69 लाख गाड़ियां बेचीं? फोर्ड इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डेविड फ्राइडमैन कहते हैं, ''हां, दिलचस्पी पैदा होती है। भारत तेजी से बढ़ते ऑटो बाजारों में है।''

वैसे संख्या इतनी ज्यादा नहीं है। भारत में सालाना केवल 7,00,000 कारें बिकती हैं। यह अमेरिकी बाजार के मुकाबले बहुत कम है, जहां सालाना 1.80 करोड़ कारें बिकती हैं। पर यूरोप और अमेरिका में बिक्री स्थिर रहने से एशिया से उम्मीद बंधी है। फ्राइडमैन कहते हैं, ''चीन और भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।'' फोर्ड मोटर की उत्पादकता और लागत के मामले में प्रतिस्पर्धी निर्माण इकाई भारत में पहले से ही है। कंपनी, जिसने चेन्नई स्थित अपने कारखाने में 1,700 करोड़ रु. (36.95 करोड़ डॉलर) निवेश किया है, जल्दी ही

शोम बसु

भारतीय कार बाजार में नए मॉडलों की भरमार

बराबरी की स्थिति में पहुंचने की उम्मीद कर रही है।

फोर्ड के लिए भारत बाजार से कहीं अधिक है। फोर्ड के भारतीय कारोबार में कारों व वाहनों के कलपुर्जों के निर्यात में भी संभावनाएं हैं। फोर्ड मोटर कंपनी इस साल भारत से कलपुर्जे खरीदेगी और धीरे-धीरे यह खरीद बढ़ाएगी। फ्राइडमैन कहते हैं, ''दुनिया के बड़े वाहन निर्माताओं के सामने लागत घटाने की चुनौती है। भारत अच्छा विकल्प है।'' फोर्ड ने भारत की आईटी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए अपने अंतरराष्ट्रीय कारोबार की खातिर इंजीनियरिंग और सूचना एप्लिकेशन डिजाइन करने के लिए आईटी शाखा भी बनाई है। फोर्ड ने अपने वैश्विक कारोबार की एकाउंटिंग जरूरतों के लिए एक बिजनेस सेंटर भी स्थापित किया है। हाल के अरसे में फोर्ड वैश्विक स्तर पर जारी किए जाने वाले फोर्ड मोंडियो जैसे उत्पादों का भारत में परीक्षण भी कर रही है।